

बिहार में महिलाओं को मिलेंगे 20 हजार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने लिया बड़ा फैसला

- ▶ 10 हजार के बाद अब 20 हजार, जॉर्न जरूरी शर्त
- ▶ 70 प्रतिशत महिलाओं ने शुरू किया काम



तैयारी की जा रही है. हालांकि, यह राशि सभी को नहीं मिलेगी. सरकार ने इसके लिए एक अहम शर्त तय की है—केवल वही महिलाएं इस किस्त की पात्र होंगी, जिन्होंने पहली किस्त में मिले 10 हजार रुपये का उपयोग कर वास्तव में कोई रोजगार शुरू किया है।

योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार किया शुरू

राज्य की सहयोगी संस्था जीविका द्वारा किए गए सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू किया है. यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो रही है. प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, करीब 70 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी रूप में रोजगार शुरू कर लिया है. इनमें पशुपालन, किराना दुकान, सब्जी-फल विक्रय, सिलाई-कढ़ाई, चाय-पकौड़ी की दुकान और ब्यूटी पार्लर जैसे छोटे व्यवसाय शामिल हैं. सरकार अब उन महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है, जिनका काम सही तरीके से चल रहा है और जिनकी आय में स्थिरता आई है. योजना के तहत आर्थिक सहायता चरणबद्ध तरीके से दी जाती है. पहली किस्त 10 हजार रुपये की दी जा चुकी है. दूसरी किस्त 20 हजार रुपये की होगी, जिसमें लाभार्थी को कुछ अंशदान भी करना होगा. इसके बाद तीसरी और चौथी किस्त क्रमशः 40 हजार और 80 हजार रुपये की होगी, जबकि अंतिम चरण में 60 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी. विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता का भी प्रावधान है.

राष्ट्रपति मुर्मु आज ओडिशा के दौर पर



नयी दिल्ली 20 अप्रैल. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मंगलवार को ओडिशा का दौरा करेंगी. राष्ट्रपति भवन की विज्ञापित के अनुसार श्रीमती मुर्मु राउरकेला में एक सार्वजनिक समारोह में तारामंडल और विज्ञान केंद्र तथा निर्मल मुंडा परिवेश पथ का उद्घाटन करेंगी. वह राउरकेला में एक जनजातीय संग्रहालय और एकोकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन करेंगी.

शिक्षित हो रहे साइबर ठगी के शिकार

डिजिटल अरेस्ट केस पर सीजेआई सूर्यकांत ने जताई चिंता



नई दिल्ली, 20 अप्रैल. देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर चिंता जताई है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने डिजिटल अरेस्ट केस पर साइबर फ्रॉड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद हैरान करने वाली बात है कि पढ़े-लिखे और जागरूक लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं. उन्होंने एक ऐसे मामले का उल्लेख किया जिसमें एक बुजुर्ग महिला से उनकी पूरी सेवानिवृत्ति राशि टाग ली गई. उन्होंने ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए महिला को डराया और उसे डिजिटल गिरफ्तारी का झांसा देकर पूरी तरह मानसिक रूप से दबाव में ले

उनकी पूरी सेवानिवृत्ति राशि साइबर ठगों ने हड़प ली. ठगों ने खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को वीडियो कॉल के जरिए डराया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह किसी गंभीर कानूनी मामले में फंस गई है. इसी दबाव में महिला ने अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी. इस मामले की सुनवाई के दौरान अर्जेंटो जर्नल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है. इसके बाद अदालत ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मई को निर्धारित की है.

नारी सब कुछ भूलती है लेकिन अपमान नहीं

महिलाओं का विद्रोह नहीं ये कांग्रेस का विध्वंस है : सीएम डॉ. मोहन यादव

नवभारत प्रतिनिधि भोपाल, 20 अप्रैल. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और बेजेपी ने नारी शक्ति चंदन विधेयक गिरने के बाद विपक्ष पर ठीकरा फोड़ते हुये कहा कि कांग्रेसियों ने महिलाओं का अपमान किया है. उन्होंने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और विपक्ष नेता राहुल गांधी सहित समाजवादी पार्टी, टीएमसी व डीएमके जैसे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुये कहा कि इन विपक्षी दलों ने विधेयक को गिराकर महिला के अधिकारों का गला घोटने का काम किया है. एमवीएम ग्राउंड में आयोजित नारी सशक्तिकरण सम्मेलन कार्यक्रम में डॉ मोहन यादव ने विपक्ष पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुये महिला आरक्षण बिल को विफलता पर आक्रोश व्यक्त किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन



यादव सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कवियित्री अनामिका अंबर, सांसद लता वानखेडे, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनिस, मंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय सहित कई गणमान्य नेताओं ने एक साथ मंच

साझा करते हुए विधेयक गिरने को महिलाओं का अपमान बताते हुये जमकर हल्लाबोल किया. इस अवसर पर डॉ मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की कोशिश कर रही है. लेकिन वो ये नहीं जानते ये नारी सब कुछ भूलती है

गिराकर उनका अपमान कर कांग्रेस ने बहनों के अधिकारों को फांसी देने का काम किया है. इन्होंने हमेशा ही महिला अधिकारों को सत्ता की आड़ में कुचलने का और गला घोटने का काम किया है. लेकिन वो ये नहीं जानते ये नारी सब कुछ भूलती है

लेकिन अपमान नहीं, इसका बदला लिया जाएगा. डॉ यादव ने कहा कि 40 साल पहले भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हमारी बहनों के जीवन में 3 तलाक लाकर उनके अधिकारों पर डाका डाला था और अब एक बार फिर से इन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया

है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश की आधी आबादी को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार देना चाहती थी. लेकिन विपक्ष को ये मंजूर नहीं है. आज हर जिले के नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत में निंदा प्रस्ताव लाये. वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति चंदन विधेयक को लोकसभा में गिराकर ये साबित कर दिया है कि उन्हें देश की बहनों का सम्मान और अधिकार मंजूर नहीं है. इसलिए जब भी और जहां भी मौका मिले इन कांग्रेसियों से पूछिए कि इन्हें किसने अधिकार दिया है महिलाओं का अपमान करने का, इन्हें किसने अधिकार दिया है महिलाओं की समानता और उनकी बुलंद आवाज को दबाने का. उन्होंने कहा कि जो लोग बहनों के अपमान में जश्न मना रहे हैं, आने वाले समय में उनसे बदला लिया जाएगा. कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री समेत हेमंत खंडेलवाल,

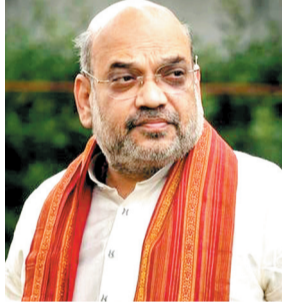
कृष्णा गौर और अर्चना चिटनिस सहित कई नेताओं ने कुछ दूर तक महिला पद यात्रा की अगुवाई भी की. जो कि एमवीएम ग्राउंड से शुरू होकर रौशनपुरा चौराहे पर समाप्त हुई.



एक दिन में 53.5 लाख एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 20 अप्रैल. वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने घरेलू स्तर पर ईंधन आपूर्ति को लेकर मजबूत नियंत्रण का संकेत दिया है. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 के देशभर में 53.5 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की गई, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इस दौरान खास बात यह रही कि लगभग 98 प्रतिशत एलपीजी बुकिंग डिजिटल माध्यमों के जरिए की गई, जिससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और तेजी दोनों आई है. सरकार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू गैस सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं आई है.

नशा तस्करो का होगा सफाया : शाह



नयी दिल्ली 20 अप्रैल. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अनुराग शाह ने सोमवार को कहा कि युवाओं को नशे के अभिशाप से बचाने के लिए सरकार नशा तस्करी के गिरोहों का निर्मूलना से सफाया कर रही है और उनकी दोषसिद्धि सुनिश्चित भी कर रही है. शाह ने वर्ष 2026 के पहले तीन महीनों में 73 मादक पदार्थ अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर कहा कि हमारे युवाओं को नशीले पदार्थों की महामारी से बचाने के लिए मोदी सरकार

दुबारा से इन कार्टलों का सफाया कर रही है और उनकी सजा सुनिश्चित कर रही है. इस मिशन के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2026 के पहले तीन महीनों में 73 इन अपराधियों को दोषी ठहराकर सख्त से सख्त सजा दिलाई है. इस दूर रिकेटों की सीस तने की हर एक जगह बंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ संचालन है. एनसीबी को इस उपलब्धि के लिए बधाई है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक, एनसीबी ने 35 मामलों में 73 इन

अपराधियों को दोषी करार दिया है. इनमें से चार अपराधियों को अधिकतम 20 वर्ष की सजा सुनाई गई, जबकि 54 अन्य को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई. दोषियों पर कुल 1.22 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. एनसीबी की मुकदमों की निगरानी पर केंद्रित रणनीति के कारण दोषसिद्धि दर में निरंतर वृद्धि हुई है. यह दर वर्ष 2024 में 60.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 65.5 प्रतिशत हो गई और अब वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 68.6 प्रतिशत पहुंच गई है.

व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा



रियाद, 20 अप्रैल. तेजी से बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल के बीच भारत अपनी कूटनीतिक सक्रियता को नए स्तर पर ले जा रहा है. इसी क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का सऊदी अरब दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

मुस्तैद अल एब के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इन वार्ताओं में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे. इमारतीय दृष्टावस के अनुसार, दोनों पक्षों ने साझा हितों से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा की और आपसी सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और सऊदी अरब की यह बातचीत विशेष महत्व रखती है. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है.



सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रपुत्र' होने का मांग खारिज

नई दिल्ली, 20 अप्रैल. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करने और आजाद हिंद फौज को भारत की आजादी का श्रेय देने संबंधी जनहित याचिका खारिज कर दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता पिनाकपानी मोहंती को कड़ी फटकार लगाते हुए 'न सुधरने वाला' बताया.

स्टालिन के लिए केजरीवाल करेंगे प्रचार

चेन्नई में केजरीवाल-स्टालिन की मुलाकात, सियासत गरम



चेन्नई, 20 अप्रैल. तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन की चेन्नई में हुई मुलाकात ने विपक्षी एकजुटता को नया संकेत दिया है. यह बैठक ऐसे समय पर हुई है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. केजरीवाल ने इस मुलाकात के दौरान साफ किया कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन करेगी. उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर दोनों दलों के साझा विजन की बात कही. इस मुलाकात को केवल औपचारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है. एक तरफ जहां यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी सहयोग को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर यह संकेत भी देती है कि

भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही: राहुल



चेन्नई, 20 अप्रैल. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह चुनावी लड़ाई भाजपा की बांटने वाली राजनीति का विरोध करने, उसे हराने और पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने के खिलाफ है. श्री गांधी ने कन्याकुमारी जिले के दक्षिणी छोर पर स्थित कोलांचल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और तमिलनाडु में भी वही हथकंडे अपना रही है ताकि अपने सहयोगी अखिल भारतीय अज्ञा द्रविड़ मुन्नेत्र कषमम (अनाद्रमुक) के जरिए दिल्ली से राज्य पर शासन कर सके. अनाद्रमुक ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से इस भगवा पार्टी के सामने चुटने टुक दिए हैं. उन्होंने कहा कि इसका फायदा उठाकर आरएसएस परीक्षक रूप से राज्य पर शासन करने की कोशिश कर रही है. भारत को एकजुट करने के लिए इसी जल्लि से शुरू की गई अपनी ५% भारत छोड़ो यात्रा ५% को याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सभी राज्यों को समान महत्व मिलना चाहिए और हर भाषा के पीछे एक इतिहास होता है, ठीक वैसे ही जैसे तमिल भाषा का इतिहास हजारों साल पुराना है. श्री गांधी ने यह कहते हुए कि संविधान राज्यों के लोगों को ही अपने राज्य पर शासन करना चाहिए. तमिलनाडु पर भी उसके अपने लोगों का ही शासन होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भारत के हर राज्य को यह तय करने का अधिकार है, जैसा कि संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है.

उद्घाटन भारत एक जीवंत परंपरा है- वह आधारशिला जिस पर जीवन की निरंतरता टिकी हुई है

भागवत ने संस्कृत को बताया राष्ट्र की आत्मा

लोगों से की संस्कृत सीखने की अपील



नई दिल्ली 20 अप्रैल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने संस्कृत को राष्ट्र की आत्मा बताते हुये लोगों से इसे सीखने की अपील की है. श्री भागवत ने दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित संस्कृत भारतीय के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर सोमवार को कहा कि संस्कृत भारतीय एक ऐसी संस्कृति है जो संस्कृत को एक जीवंत और व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए समर्पित

के दिन जो कार्य प्रारंभ होते हैं, वह अक्षुण्ण रहते हैं. यही बात संस्कृत के बारे में कहा गया है. कभी न क्षय होने वाला आभूषण संस्कृत है. उसका कार्यालय अपने आप में यह संदेश दे रहा है. कार्यालय के उद्घाटन में उसके आनंद उत्साह में कार्य का भाव भी स्थिर होना चाहिए. रूचि के साथ प्रयोजन भी हो तो कार्य अच्छा और निरंतर होता है. साधन नहीं अवस्था में कार्य आरम्भ होना है. उन्होंने कहा कि संस्कृत एक भाषा है. फिर भी यह मात्र एक भाषा नहीं है. भारत में संस्कृत राष्ट्र की आत्मा है क्योंकि यह विचार, जीवन और संस्कृति को सबसे प्राचीन परंपरा है.

एक ऐसी परंपरा जो आज भी जीवंत है जो भारत में विद्यमान है. उन्होंने भारत के दार्शनिक विचार को और विस्तार से समझाते हुए कहा कि भारत का अस्तित्व मात्र एक भौगोलिक तथ्य नहीं है. यह महज एक राजनीतिक या आर्थिक इकाई नहीं है. भारत एक जीवंत परंपरा है- वह आधारशिला जिस पर जीवन की निरंतरता टिकी हुई है. संघ प्रमुख ने संस्कृत भाषा के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बचपन में जब स्कूल में संस्कृत पढ़ाई जाती थी, तो यह कठिन लगती थी.

मतदान से पहले 135 व्यक्ति गिरफ्तार

कोलकाता, 20 अप्रैल. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई में चार जिलों से आपराधिक पृष्ठभूमि और आपराधिक आरोपों वाले 135 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इन चार जिलों में 23 अप्रैल को चुनाव के पहले चरण में मतदान होने है. ये गिरफ्तारियां कूचबिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना सहित चार जिलों में रातों-रात चलाये गये एक अभियान के दौरान की गईं. ये गिरफ्तारियां चुनाव आयोग के उन निर्देशों के बाद हुई हैं, जिसमें राज्य पुलिस को प्रदेश भर के थानों में विहित उपद्रवियों, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों और लक्षित मामलों वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था.

टीएमसी कार्यकर्ता को मारी गोली

देर रात हमला, टीएमसी कार्यकर्ता की हालत गंभीर

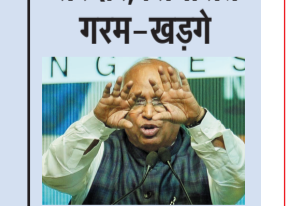
चुनावी माहौल में गोलीकांड से बढ़ा तनाव

कोलकाता, 20 अप्रैल. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसा की घटनाएं एक बार फिर सुर्खियों में हैं. साउथ 24 परगना जिले में तुणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है. घटना उस समय हुई जब कार्यकर्ता पार्टी मीटिंग से देर रात अपने घर लौट रहा था। अचानक घात लगाकर बंदे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें उनकी हालत नजुक बनी हुई है. इस घटना के बाद सियासत भी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

तेज हो गई है। तुणमूल कांग्रेस ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों के मूताबिक, पहली गोली उनकी दाहिनी जांच में लगी, जिससे वह बाइक से गिर पड़े। इसके बाद हमलावरों ने उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल कार्यकर्ता को तुरंत कैनिंग सब-डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें वितरजन नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

पीएम झुठों के सरदार, सियासत गरम-खड़ो



कोलकाता/चेन्नई, 20 अप्रैल. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है. मल्लिकार्जुन खड्गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोले हुए उन्हें झुठों का सरदार तक कह दिया. उनके इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है. दूसरी ओर, असम के मुख्यमंत्री हिमांत बिस्वा सरमा ने भी पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान विवादित बयान देकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया.